

राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या  
अहवाल खंड-१ मधील वेतनश्रेणीबाबतच्या व  
आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत  
करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन  
वित्त विभाग  
शासन निर्णय, क्रमांक: वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९  
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.  
दिनांक :- १ जानेवारी, २०१९

**प्रस्तावना:-**

केंद्र शासनाने केंद्रीय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयांच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक वेपुर-१२१६/प्र.क्र.५८/सेवा-९, दि. १७ जानेवारी, २०१७ अन्वये श्री. के. पी. बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ स्थापन करण्यात आली होती. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपल्या अहवालाचा खंड - १ शासनास दि. ५ डिसेंबर, २०१८ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

**शासन निर्णय:-**

शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालाच्या खंड - १ मधील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्रात नमूद करण्यात आला आहे. प्रस्तुत शिफारशी स्वीकृत करण्याच्या परिणामस्वरूप ज्याप्रकरणी सविस्तर आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता आहे, त्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०११७०५४५०६०५ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(नितीन गद्रे)

प्रधान सचिव, (ले. व को.) वित्त विभाग

प्रति,

<p>राज्यपालांचे सचिव मुख्यमंत्री यांचे सचिव अध्यक्ष /उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव सभापती/ उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई मंत्रालयीन सर्व विभाग मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख # प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. # प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. # सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. # सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. # प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. # आयुक्त राज्य माहिती आयोग, (सर्व) # सचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. # प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/ औरंगाबाद. राज्य महिला आयोग, वरळी, मुंबई. सर्व विभागीय आयुक्त. सर्व जिल्हाधिकारी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवान, पुणे</p>	<p>निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई / नागपूर / पुणे / औरंगाबाद. मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी / देहू रोड/ देवळाली/ अहमदनगर. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर कुलसचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला कुलसचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, नागपूर. कुलसचिव, पुणे विद्यापीठ, पुणे. कुलसचिव, पुणे विद्यापीठ, पुणे कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई.  महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई  महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर  महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर  सिनियर रिसर्च ऑफीसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली  संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.  अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,  निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.  जिल्हा लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी हिशेब, सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.  सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद.  मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी/देहूरोड/देवळाली/अहमदनगर  कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर  कुलसचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी  कुलसचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी.  कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला  कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई</p>	<p>कुलसचिव, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव  कुलसचिव, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर  कुलसचिव, महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर  कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड  मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी हिशेब, मुंबई  उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी हिशेब, मुंबई/पुणे/नागपूर/ औरंगाबाद/नाशिक/ अमरावती.  बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१  भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी .ओ., बॅरक क्रमांक १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२०  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३  इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५  नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१  शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८  वित्त विभागातील सर्व कार्यासने निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-९)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: वेपुर-२०१८/प्र. क्र. ४४/सेवा-९, दिनांक :- १ जानेवारी,  
२०१९ सोबतचे जोडपत्र )

जोडपत्र

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्या आणि महागाई भत्त्यासंदर्भातील  
शिफारशीबाबतचे निर्णय

अ. क्र.	अहवालातील परिच्छेद क्रमांक	शिफारशीचा गोषवारा	शासनाने घेतलेले निर्णय
१	४.१	वेतन मॅट्रिक्स आधारीत सुधारित वेतनश्रेण्या	
		केंद्र शासनाने ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्वीकारलेली वेतन मॅट्रिक्स संरचनेची संकल्पना राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी दिनांक १.१.२०१६ पासून लागू करण्याची समिती शिफारस करीत आहे.	शिफारस स्वीकृत.
२	४.२	असुधारित वेतनसंरचनांचे विलिनीकरण	
	४.२.३	७ व्या वेतन आयोगात सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील दोन स्तरांमध्ये पुरेसा फरक रहावा हा दृष्टीकोन ठेवून, तसेच परिच्छेद ४.२.२ मध्ये नमूद ग्रेड वेतने आधारभूत मानून आणि परिच्छेद ४.२.४ मध्ये नमूद ७ वेतन संरचनांचे (ग्रेड वेतनांचे) विलिनीकरण करून त्यांना सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये समकक्ष स्तराची शिफारस करण्यात येत आहे	शिफारस स्वीकृत.  मात्र यामुळे पदोन्नतीचे संवर्ग आणि निम्न संवर्गास एकच वेतन स्तर अनुज्ञेय झाल्यास या दोन्ही संवर्गांच्या वेतनमानात फरक ठेवणे आवश्यक राहील. याबाबत राज्य वेतन सुधारणा समितीने अहवालाच्या खंड २ मध्ये विचार करावा.

अ. क्र.	अहवालातील परिच्छेद क्रमांक	शिफारशीचा गोषवारा	शासनाने घेतलेले निर्णय
	४.४	<p>६ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर नियुक्त केलेल्या वेतनव्रुटी निवारण समितीच्या शिफारशीनुसार रु. ८००० - १३५०० या वेतनश्रेणीतील गट - ब संवर्गास वेतनबँड पीबी - ३ : रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५४०० ही वेतन संरचना मंजूर केली आहे. ज्या संवर्गाचे या संबंधीचे प्रस्ताव वेतनव्रुटी समितीच्या विचारार्थ सादर झाले नव्हते, त्या संवर्गांना मात्र वेतनबँड पीबी - ३: रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५४०० या वेतन संरचनेचा लाभ मिळू शकला नाही.</p> <p>वेतनव्रुटी समितीने स्वीकारलेला दृष्टीकोन योग्य वाटत असल्याने आता समिती वेतनबँड पीबी - ३ : रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५४०० आणि वेतनबँड पीबी - २ : रु. ९३०० + ग्रेड वेतन रु. ५४०० या असुधारित वेतन संरचनांसाठी सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये एकच स्तर एस -२० ची शिफारस करत आहे.</p>	वरील परिच्छेद क्रमांक ४.२.३ प्रमाणे शिफारस स्वीकृत.
३	४.५	<b>सुधारित वेतन मॅट्रिक्स</b>	
		<p>६ व्या वेतन आयोगातील विद्यमान वेतन संरचनांसाठी तक्ता क्र. ४.१ मधील सुधारित वेतन मॅट्रिक्सची शिफारस करण्यात येत आहे.</p> <p>सर्व राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून त्यांच्या विद्यमान वेतनसंरचनांशी समकक्ष वेतन स्तर मंजूर करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.</p> <p>मात्र परिच्छेद ४.६ मध्ये नमूद संवर्गांच्या बाबतीत त्या परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे वेतन स्तर मंजूर करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.</p>	शिफारस स्वीकृत.

अ. क्र.	अहवालातील परिच्छेद क्रमांक	शिफारशीचा गोषवारा	शासनाने घेतलेले निर्णय										
४	४.६	महिला व बालविकास विभाग, जलसंपदा विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (अकृषि विद्यापीठे) या मधील काही संवर्गांच्या सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तरांविषयी शिफारशी											
	४.६.१	महिला व बालविकास विभाग — समुपदेशक वेतनबँड पीबी-२: रु. ९३००-३४८०० + रु. ४२०० ग्रेड वेतन आणि वेतनबँड पीबी-२: रु. ९३००-३४८०० + रु. ४३०० ग्रेड वेतन या दोन्ही वेतन संरचनेतील समुपदेशक या संवर्गास सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये एकच वेतन स्तर एस-१३ मंजूर करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.	शिफारस स्वीकृत.										
		<b>जलसंपदा विभाग</b>  <b>(अ) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक</b>  <b>(ब) पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे</b>  दि. २५ जुलै, २०१४ आणि दि. ३० जून, २०१६ रोजीच्या अधिसूचना रद्द करून वरील दोन्ही आस्थापनांवरील प्रत्येकी तीनही संवर्गांना पुढीलप्रमाणे वेतनसंरचना मंजूर करण्याची समिती शिफारस करीत आहे:- <table> <tr> <th>अ. क्र.</th> <th>संवर्गाचेनाव</th> <th>६ व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनसंरचना</th> <th>वेतनबँड (रु.)</th> <th>ग्रेडवेतन (रु.)</th> </tr> <tr> <td>१</td> <td>वैज्ञानिक अधिकारी / उप</td> <td>९३००-३४८००</td> <td>४६००</td> <td></td> </tr> </table>	अ. क्र.	संवर्गाचेनाव	६ व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनसंरचना	वेतनबँड (रु.)	ग्रेडवेतन (रु.)	१	वैज्ञानिक अधिकारी / उप	९३००-३४८००	४६००		शिफारस स्वीकृत.
अ. क्र.	संवर्गाचेनाव	६ व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनसंरचना	वेतनबँड (रु.)	ग्रेडवेतन (रु.)									
१	वैज्ञानिक अधिकारी / उप	९३००-३४८००	४६००										

अ. क्र.	अहवालातील परिच्छेद क्रमांक	शिफारशीचा गोषवारा	शासनाने घेतलेले निर्णय												
		<table border="1"> <tr> <td></td><td>मृद सर्वेक्षण अधिकारी</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>२</td><td>वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक</td><td>९३००-३४८००</td><td>४५००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक</td><td>९३००-३४८००</td><td>४४००</td></tr> </table> <p>वरील परिच्छेदामध्ये शिफारस केल्याप्रमाणे ६ व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनसंरचना मंजूर करून पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:-</p> <p>संबंधित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. १ जानेवारी, २००६ पासून आता शिफारस केलेल्या वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्यात यावी. मात्र अतिप्रदानाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये. तसेच आता शिफारस केलेल्या ६ व्या वेतन आयोगाच्या वेतनसंरचना आधारभूत मानून ७ व्या वेतन आयोगात तक्ता क्रमांक ४.१ मध्ये नमूद केलेल्या सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील समकक्ष वेतन स्तर मंजूर करण्यात यावा.</p>		मृद सर्वेक्षण अधिकारी			२	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक	९३००-३४८००	४५००	३	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक	९३००-३४८००	४४००	
	मृद सर्वेक्षण अधिकारी														
२	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक	९३००-३४८००	४५००												
३	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक	९३००-३४८००	४४००												
	४.६.३	उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (अकृषि विद्यापीठे)													
		<p>सर्व विद्यापीठांत शिक्षकेतर पदांच्या ६ व्या वेतनआयोगानुसार मंजूर केलेल्या वेतनश्रेण्यांची तपासणी करून संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांकडून झालेले अतिप्रदान वसूल करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.</p> <p>तसेच योग्य त्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील ज्या पदनामांमध्ये व वेतनश्रेण्यांमध्ये नियमबाह्य बदल केल्यामुळे शासनाचे नुकसान झालेले आहे, अशी सर्व पदनामे व त्या पदांना मंजूर केलेल्या वेतनश्रेण्या ७ व्या वेतन आयोगानुसार</p>	<p>शिफारस स्वीकृत.</p> <p>उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून योग्य त्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांतील ज्या पदनामांमध्ये व वेतनश्रेण्यांमध्ये नियमबाह्य बदल</p>												

अ. क्र.	अहवालातील परिच्छेद क्रमांक	शिफारशीचा गोषवारा	शासनाने घेतलेले निर्णय
		सुधारित करण्यापूर्वीच दिनांक ७.१०.२००९ च्या शासन अधिसूचनेनुसार कटाक्षाने पूर्ववत करण्याची कार्यवाही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तातडीने करावी, तसेच अशा अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर त्वरीत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस समिती करीत आहे.	केल्यामुळे शासनाचे नुकसान झालेले आहे, अशी सर्व पदनामे व त्या पदांना मंजूर केलेल्या वेतनश्रेण्या ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यापूर्वीच दिनांक ७.१०.२००९ च्या शासन अधिसूचनेनुसार कटाक्षाने पूर्ववत करण्याची कार्यवाही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तातडीने करावी, तसेच अशा अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर त्वरीत शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
५	४.७	मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी सुधारित वेतन स्तर	
		मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरूप विचारात घेऊन मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गास विद्यमान वेतनबँड पीबी - १ + ग्रेड वेतन रु. १९०० या वेतन संरचनेतील एस-६ रु. १९९००-६३२०० या सुधारित वेतन मॅट्रिक्स ऐवजी एस-८ या वेतन मॅट्रिक्समधील रु. २५५००-८११०० हा वेतनस्तर मंजूर करण्याची समिती शिफारस करीत आहे.	या शिफारसीबाबत स्वतंत्रपणे अभ्यास करून नंतर उचित निर्णय घेण्यात येईल.



अ. क्र.	अहवालातील परिच्छेद क्रमांक	शिफारशीचा गोषवारा	शासनाने घेतलेले निर्णय
६	४.८	सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये वेतननिश्चिती	
		<p>राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांची दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये पुढीलप्रमाणे वेतननिश्चिती करण्यात यावी:-</p> <p>विद्यमान वेतन संरचनेत दि. १ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या मूळ वेतनास (वेतनबँडमधील वेतन + ग्रेड वेतन) २.५७ ने गुणून नजीकच्या रुपयामध्ये पूर्णांकित (Rounding off) केलेली रक्कम संबंधित संवर्गास/पदास सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये अनुज्ञेय वेतन स्तरामधील सेलमध्ये (Cell) असल्यास ती रक्कम सुधारित वेतन ठरेल. जर ती रक्कम वेतन स्तरामधील सेलमध्ये नसेल तर सदर पूर्णांकित रकमेच्या लगतच्या पुढील सेलमधील रक्कम सुधारित वेतन ठरेल.</p>	<p>शिफारस स्वीकृत.</p> <p>तसेच जे कर्मचारी दि. १ जानेवारी, २०१६ रोजी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत मंजूर वेतनश्रेणीत वेतन घेत असतील, अशा कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती त्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत अनुज्ञेय समकक्ष सुधारित वेतन स्तरामध्ये करण्यात यावी.</p>
७	४.९	सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतनवाढीचा दिनांक	
		<p>विद्यमान वेतन संरचनेतील १ जुलै या वेतनवाढीच्या दिनांकाऐवजी सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये १ जानेवारी किंवा १ जुलै असे दोन वेतनवाढीचे दिनांक असतील. कर्मचाऱ्यास त्याची नियुक्ती / पदोन्नती किंवा आर्थिक श्रेणीवाढ या बाबी विचारात घेऊन १ जानेवारी किंवा १ जुलै यापैकी एक वेतनवाढीचा दिनांक अनुज्ञेय होईल.</p>	शिफारस स्वीकृत.
८	४.१०	विशेष वेतन	
		६ व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सुधारित	शिफारस स्वीकृत.

अ. क्र.	अहवालातील परिच्छेद क्रमांक	शिफारशीचा गोषवारा	शासनाने घेतलेले निर्णय
		वेतनसंरचना लागू केल्यानंतर सर्व संवर्गांचे विशेष वेतन बंद करण्यात आले होते. तथापि पोलीस शिपाई, नाईक आणि हवालदार या संवर्गांशी निगडीत कर्तव्यांचे स्वरूप विचारात घेऊन त्या संवर्गांचे विद्यमान रु. ५०० दराने मिळत असलेले विशेष वेतन पुढे चालू ठेवण्यात आले होते. सदर विशेष वेतनात ५० % वाढ करून ते यापुढेदेखील सुरु ठेवण्याची समिती शिफारस करीत आहे.	
९	४.११	<b>नियत/एकत्रित वेतनावरील अंशकालिन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा</b>	
		<p>सर्वसाधारणपणे ज्या कामांसाठी अंशकालिन कर्मचारी नियुक्त केले जातात अशी कामे आता बाह्यस्रोतामार्फत करण्याचे शासनाचे प्रचलित धोरण असल्याने नव्याने अंशकालिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे अपेक्षित नाही. मात्र कार्यरत अंशकालिन कर्मचाऱ्यांच्या नियत/एकत्रित वेतनात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.</p> <p>शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. वेपुर-१२०९/प्र.क्र.२०/सेवा-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ अन्वये नियत/एकत्रित वेतनावरील अंशकालिन कर्मचाऱ्यांचे वेतन दुप्पट करून ते किमान रु. ६०० आणि कमाल रु. १२०० इतके करण्यात आले आहे. अंशकालिन कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे नियत/एकत्रित दरमहा वेतन अडीच पट करण्यात यावे, ही वाढीव रक्कम किमान रु. १५०० आणि कमाल रु. ३५०० या मर्यादेत राहिल, अशी समितीची शिफारस आहे.</p>	शिफारस स्वीकृत.
१०	४.१२	<b>महागाई भत्ता</b>	
		केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि. १.१.२०१६ पासून लागू करण्यात आलेले महागाई भत्त्याचे दर राज्य	<p>शिफारस स्वीकृत.</p> <p>केंद्र शासनाने वेळोवेळी मंजूर केल्याप्रमाणे</p>

अ. क्र.	अहवालातील परिच्छेद क्रमांक	शिफारशींचा गोषवारा	शासनाने घेतलेले निर्णय
		शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावेत.	महागाई भत्ता कार्यरत तसेच सर्व निवृत्तिवेतनधारकांना मंजूर करण्यात यावा.
११	४.१३	<b>शिफारशींची व्याप्ती</b>	
		या प्रकरणातील शिफारशी पात्र राज्य शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, न्यायालयातील अन्यायिक कर्मचारी, अनुदानित शाळेतील कर्मचारी, कृषि व अकृषि विद्यापीठे आणि त्यांना संलग्न अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयातील कर्मचारी तसेच इतर अनुदान प्राप्त संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना लागू होतील. या शिफारशी इतर कार्यालयांतील / संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा दिनांक राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावा, अशी समिती शिफारस करीत आहे.	शिफारस स्वीकृत. या शिफारशी शासनाने ६ वा वेतन आयोग लागू केलेल्या व वेतन अनुदान मिळणाऱ्या इतर अनुदान प्राप्त संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात याव्यात.
१२	४.१४	<b>अंमलबजावणीचा दिनांक</b>	
		राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन स्तर अनुज्ञेय करण्यात यावेत आणि शिफारस केलेल्या वेतननिश्चितीच्या सूत्रानुसार वेतननिश्चिती करण्यात यावी.	शिफारस स्वीकृत.
१३	७.१	दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीसाठी वेतन व निवृत्तिवेतन सुधारित केल्यामुळे थकबाकीची रक्कम समान हप्त्यात अदा करण्यात यावी. निवृत्तिवेतनधारकांना अनुज्ञेय असणारी थकबाकीची रक्कम कमीत कमी हप्त्यात अदा करण्यात यावी, अशी समिती शिफारस करीत आहे.	शिफारस स्वीकृत. सुधारित वेतनश्रेणीविषयक व आनुषंगिक लाभ या बाबतच्या शिफारशी दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून लागू करण्यास

अ. क्र.	अहवालातील परिच्छेद क्रमांक	शिफारशीचा गोषवारा	शासनाने घेतलेले निर्णय
			<p>मान्यता देण्यात येत आहे.</p> <p>सुधारित वेतनश्रेण्यांनुसार वेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि. १ जानेवारी, २०१९ पासून देण्यात यावेत.</p> <p>सुधारित वेतन निश्चितीच्या परिणामी दि. १ जानेवारी, २०१६ ते दि. ३१ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीतील अनूज्ञेय थकबाकी पुढील आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षांत ५ समान हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी / प्रकरणपरत्वे उचित निवृत्तिवेतन योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. सदर रक्कम जमा केल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षे काढून घेता येणार नाही.</p>

\*\*\*\*\*